क्रांति समय
हिन्दी दैनिक अखबार में विज्ञापन, प्रैस नोट, जन्म दिन की शुभकामनाएँ, या अपने विस्तार में किसी भी समस्या को अखबार में प्रकाशित करने के लिए संपर्क करें:-
बी-4 घंटी वाला कॉम्पलेक्ष उधना तीन रास्ता, उडुप्पी होटल के बगल में, सूरत-394210
मो. 9879141480

दैनिक
क्रांति समय

RNI.No. : GUJHIN/2018/75100

क्रांति समय
हमारे यहां पर एल.आई.सी., कार-बाईक-ट्रक का इन्सयोरेंशन, रेल टिकट, एयर टिकट बनवाने के लिए संपर्क करें:-
बी-4 घंटी वाला कॉम्पलेक्ष उधना तीन रास्ता, उडुप्पी होटल के बगल में, सूरत-394210
मो. 8980974047

संपादक : सुरेश मौर्या मो. 9879141480 सह संपादक : संदीप मौर्या
E-mail: krantisamay@gmail.com
सूरत, वर्ष: 1 अंक: 299, गुरुवार, 29 नवम्बर, 2018, पेज: 4, मुल्य 1 रु.
रजीस्ट्रड ऑफिस:- 191 महादेव नगर, हरि नगर-2 के पीछे, उधना, जिला-सूरत, गुजरात
Email: krantisamay@gmail.com Web site : www.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

सार समाचार

यूपी बोर्ड कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों के मांगे आधार नंबर

प्रयागराज। यूपी बोर्ड से संबद्ध स्कूलों में कक्षा 9 से 12 तक प्रवेश लेने वाले छात्र-छात्राओं के आधार नंबर मांगे गए हैं। सचिव नीना श्रीवास्तव ने मंगलवार को सभी संयुक्त शिक्षा निदेशकों और जिला विद्यालय निरीक्षकों को पत्र लिखकर आधार नंबर फीड करवाने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए एक से 31 जनवरी तक वेबसाइट खोली जाएगी। आधार नंबर अपडेट करने के साथ ही छात्र-छात्राओं के अन्य शैक्षिक विवरणों जैसे नाम की स्पेलिंग, चयनित विषय, एवं अन्य विवरण की त्रुटि आदि को भी ऑनलाइन संशोधित किया जा सकता है। राजकीय, एडेड व निजी कॉलेज के प्रधानाचार्य अपनी यूजर आईडी एवं पासवर्ड के माध्यम से आवश्यक संशोधन करेंगे। नाम में पूर्ण परिवर्तन वर्जित है जो बोर्ड स्वीकार नहीं करेगा। नाम में केवल स्पेलिंग का संशोधन ही स्वीकार होगा। पिछले साल की बोर्ड परीक्षा में फेल रहे या अग्रिम पंजीकरण कराने वाले छात्र-छात्राओं का के विवरण बोर्ड रिकार्ड से सत्यापित होकर अपडेट हुए हैं, लिहाजा इन अभ्यर्थियों के विवरण में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता।

डीए अवशेष व सातवें वेतनमान के भुगतान पर चर्चा

प्रयागराज नेशनल इंग्लिश स्कूल कटरा में मंगलवार को उत्तर प्रदेश सीनियर बेसिक शिक्षक संघ की बैठकमें शिक्षकों की लंबित मांगों, डीए अवशेष, सातवें वेतनमान का एरियर पर चर्चा हुई।

रामपुर में हाईवे पर ट्रक से भिड़ी टूरिस्ट बस, दो की मौत, 24 घायल

अमरोहा, एजेंसी। दिल्ली-लखनऊ हाईवे पर रामपुर के पास नेपाल से आ रही टूरिस्ट बस की सामने से ट्रक से भिड़ंत हो गई। इसमें नेपाल की महिला समेत दो लोगों की मौत हो गई, जबकि 24 लोग घायल हो गए। घटना से पुलिस और प्रशासन में हड़कंप मच गया। अधिकारी मौके पर पहुंचे और घायलों को अस्पताल पहुंचवाया। हादसा बुधवार को सुबह करीब साढ़े आठ बजे हुआ। नेपाल ने टूरिस्ट बस दिल्ली जा रही थी। सिविल लाइंस कोतवाली क्षेत्र में मंसूरपुर बाईपास पर सामने से आ रहे ट्रक से बस टकरा गई। हादसे में ट्रक और बस बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। बस में सवार यात्री फंस गए और चीख-पुकार मच गई। हादसे की सूचना पर पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंच गए। आनन-फानन में पुलिस की टीमें और एंबूलेंस को बुलाया गया, जिन्होंने घायलों को बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तब तक जन विश्वकर्मा पत्नी पत्नी लालबहादुर निवासी जिला संगणा नेपाल और मोहन पुत्र सुरबहादुर बटोल जिला सपनदेही नेपाल की मौत हो गई। हादसे में 24 लोग घायल हुए हैं।

उपेंद्र कुशवाहा के 'नीच' शब्द वाले आरोप पर नीतीश ने तोड़ी चुप्पी

पटना, एजेंसी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish kumar) के 'नीच' के बयान पर बिहार में मचे सियासी हलचल के बीच आखिर उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। उन्होंने सफाई देते हुए स्पष्ट किया कि मैंने क्या कहा और क्या अर्थ निकाला गया। सफाई देते हुए उन्होंने कहा कि ये मामला टीवी वालों द्वारा ज्यादा-प्रचारित किया गया। नीतीश कुमार ने कहा कि मैंने किसी पर कोई टिप्पणी नहीं की। एक निजी चैनल की तरफसे उन्हें विकास पर चर्चा के लिए बुलाया गया था और साथ ही कार्यक्रम में किसी भी राजनीतिक चर्चा को शामिल नहीं किए जाने की बात कही गई थी।

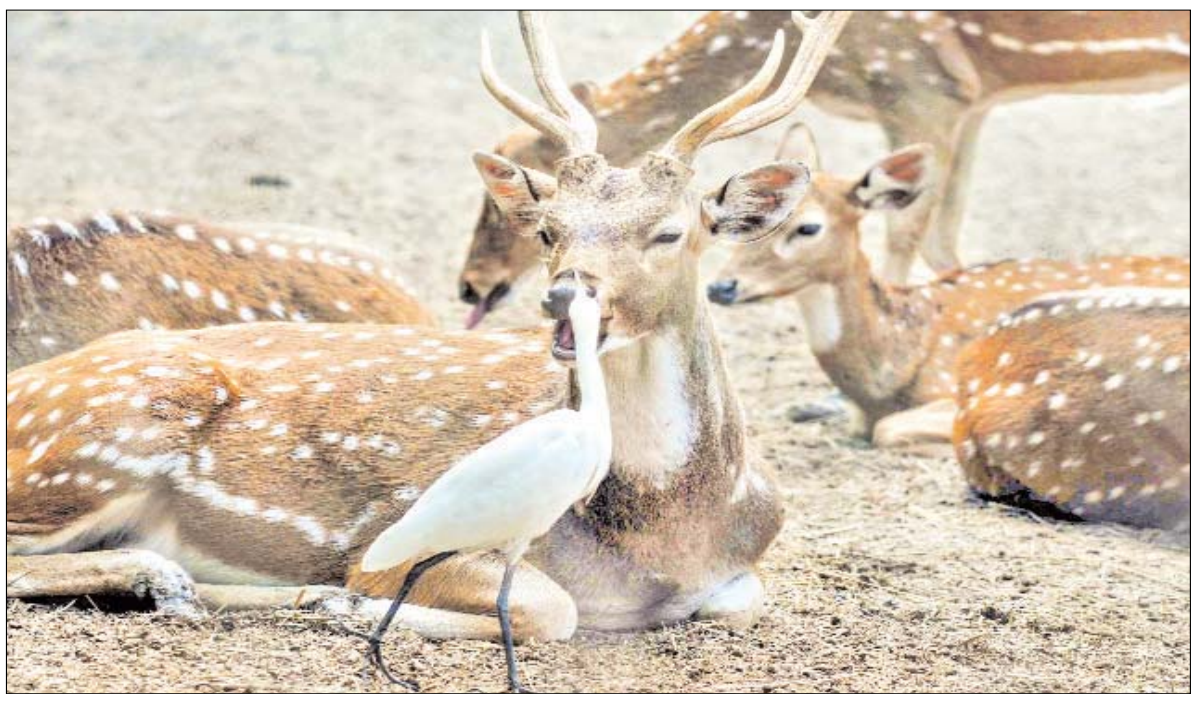

कोलकाता के अलीपोर प्राणी उद्यान में मंगलवार को अपने बाड़े में बैठे चितकबरे हिरण।

गोंडा: दो गुटों में गैंगवार, ताबड़तोड़ चली गोलियां

गोंडा, एजेंसी। बुधवार की सुबह शहर का मेवातियान मोहल्ला गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। आपसी रंजिश में दो गुट आमने सामने आ गये। एक गुट के लोगों ने दूसरे गुट के सरगना के ऊपर गोलियों से फायर कर असलहा लहराते हुए शूटर फरार हो गए। इस घटना से एक बार शहर में दहशत का माहौल है। बता दें कि शहर में महाकाल गैंग और इब्राहिम गुट अदावत जग जाहिर है। मामला शहर कोतवाली के मदरसा फुरकानिया दारुल उलूम के पास का है। बुधवार की सुबह करीब साढ़े छः बजे के आसपास दो मोटर साइकिल पर सवार चार लोग असलहा को लहराते हुए पहुचे वहां पहले से मौजूद दूसरे गुट का जुनैद भी मौजूद था। किसी तरह जुनैद अपनी जान बचाकर न्यू मेवातियाँन के बाग में पहुंचा। यहां भी मोटर साईकिल सवार शूटरों ने पीछा किया और फिर से दो फायर किया। लेकिन गोली जा के एक दुकान की शटर पर लगी। किसी तरह जुनैद ने वहां से भागकर अपनी जान बचाई। वहां मौजूद शूटर मोटर साईकिल से कब्रिस्तान मार्ग होते हुए गायत्री पुरम की ओर भाग गए।

मुठभेड़ मे गोली की आवाज़ सुनकर मोहल्ले वालों ने सूचना पुलिस को दी।

पुरानी रंजिश है दोनों गुटों मे :

महाकाल और इब्राहीम गुट मे आपसी पुरानी रंजिश चली आ रही है। दोनों गुट के लोग जब भी आमने सामने होते है तो गोलियों से ही दोनों गुटों की सलामी होती है। अभी हाल मे ही दोनों गुटों के सरगना शोभित सिंह और जुनैद किसी मामले को लेकर जेल भी गए थे अभी हाल में ही दोनों की जमानत हुई है।

आगामी लोकसभा चुनाव में मोदी की आंधी में उड़ जायेंगे विपक्षी : अमर सिंह

जंघई (जौनपुर) एजेंसी। राज्यसभा सांसद अमर सिंह ने मोदी सरकार पर अंगुलियां उठाने वाले सभी नेताओं को जहरीला सांप बताया। कहा कि ये सभी अपनी जान बचाने के लिए एकजुट होकर उनकी सरकार को बदनाम कर रहे हैं लेकिन आगामी लोकसभा चुनाव में मोदी की आंधी में सभी उड़ जाएंगे। अमर सिंह बुधवार को सर्वोदय विद्यापीठ इंटरमीडिएट कालेज मीरगंज के सर्वोदय समारोह में लोगों को संबोधित कर रहे थे। सपा, बसपा, कांग्रेस सहित अन्य दलों के नेताओं को आड़े हाथों लेते हुए जमकर लताड़ा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने देश को अंबानी और अडानी नहीं बल्कि गरीबों को उज्ज्वला, आयुष्मान बीमा योजना, जनधन योजना और गरीबों के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि अयोध्या में भगवान रामलला की पूजा अर्चना तो हो ही रही है, इसे भव्य रूप देना होगा। इसके पहले अमर सिंह अपरान्ह 2:05 पर पहुंचे और विद्यालय के संस्थापक यदुबंश सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके बाद कला भवन, पुस्तकालय एवं प्रायोगिक लैब का उद्घाटन किया। इसके पूर्व आयोजक अरुण कुमार सिंह व पुष्पेंद्र सिंह द्वारा पुष्प गुच्छ और तलवार भेंट कर उनका स्वागत किया गया।

प्रधानाचार्य डॉ. संतोष कुमार सिंह ने धन्यवाद दिया। अध्यक्षता एमएलसी चेतनारायण सिंह एवं कार्यक्रम का संचालन राजेन्द्र सिंह ने किया। इस मौके पर भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक सीमा द्विवेदी, शिवकुमार सिंह, पुष्पेंद्र सिंह सलाहकार रेलवे बोर्ड, बच्चा सिंह, हनुमंत पाण्डेय, सुबाष सिंह, कार्यक्रम आयोजक अरुण सिंह, प्रधानाचार्य डॉ. संतोष सिंह, एडवोकेट राजेन्द्र सिंह, राजीव सिंह, धीरज सिंह, राकेश कुमार यादव, शिवकुमार सिंह, गंगा सागर त्रिपाठी आदि मौजूद रहे।

यूपी में अगले साल दो छुट्टियां और कम मिलेंगी, देखिये सूची

लखनऊ, एजेंसी। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2019 के सार्वजनिक अवकाशों की सूची जारी कर दी है। राज्य कर्मचारियों को तो कई अवकाश का नुकसान उठाना पड़ेगा। यही नहीं तीन अवकाश अम्बेडकर जयंती, दीपावली व बारावफात रविवार को और गणतंत्र दिवस, रामनवमी व बुद्ध पूर्णिमा की छुट्टी शनिवार को होंगी।

सैर के लिए कई छुट्टियां एक साथ एक ओर कर्मचारियों को इस साल के विपरीत अगले साल अपेक्षाकृत कम अवकाश नहीं मिल रहे हैं तो दूसरी ओर कई पर्व शनिवार या रविवार से लग कर पड़ रहे हैं ऐसे में कर्मचारी कई दिन के लगातार अवकाश के जरिए बाहर घूमने फिरने का प्लान बना सकते हैं।

अगले साल के सार्वजनिक अवकाश के अवकाश कलैंडर के मुताबिक महानवमी सोमवार (7 अक्तूबर) व विजयदशमी मंगलवार (8 अक्तूबर) को है। शनिवार व रविवार को अवकाश है। शुक्रवार का अवकाश लेकर पांच दिन की लगातार छुट्टी ली जा सकती है।

अक्तूबर में सर्वाधिक अवकाश अक्टूबर महीने में सर्वाधिक छह पर्व हैं जिनमें अवकाश है। लेकिन दीपावली रविवार को होने के कारण एक छुट्टी की कमी हो गई। इनमें गांधी जयंती (2 अक्तूबर) , महानवमी (7 अक्तूबर) व विजयदशमी (8 अक्तूबर) दीपावली

(27 अक्तूबर), गोवर्द्धन पूजा, (28 अक्तूबर) भैया दूज / चित्रगुप्त जयंती (29 अक्तूबर) शामिल हैं।

योगी ने कई सार्वजनिक अवकाश खत्म किये

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले साल महापुरुषों की जयंती आदि पर होने वाले कई सार्वजनिक अवकाश रद्द कर दिए थे। इसमें कर्पूरी ठाकुर जयंती व महर्षि कश्यप व महाराज गुह्य जयंती (एक ही रोज), हजरत ख्वाजा मोइनुउद्दीन चिश्ती अजमेरी गरीब नवाज उर्स, चंद्रशेखर जयंती , परशुराम जयंती, महाराणा प्रताप जयंती, जमात उल विदा (रमजान माह का आखिरी शुक्रवार), छठ पर्व, व चौधरी चरण सिंह जयंती प्रमुख हैं। सचिवालय कर्मचारियों को अब ज्यादा काम यूं तो सचिवालय कर्मचारियों को पांच दिन के सप्ताह के तहत शनिवार व रविवार अवकाश मिलता है लेकिन उनका कहना है कि इसके बावजूद उन्हें अपेक्षाकृत ज्यादा घंटे काम सचिवालय में करना होता है। ऐसा इसलिए शासन के वरिष्ठ अधिकारी लंबी लंबी बैठकें करते हैं और दिन में गायब रहते हैं और शाम को आफिस में बैठते हैं, इस कारण सचिवालय में अधिकारियों के स्टाफ व अनुभाग के अधिकारियों को खासा जूझना पड़ता है। यही नहीं उच्च स्तर पर व रात में होने वाली बैठकों के कारण वरिष्ठ अधिकारी कोई रिस्क न लेते हुए अपने आफिस खुलवाये रहते हैं।

जेपी ने बकाया नहीं चुकाया तो जा सकती है फॉर्मूला वन और स्पोर्ट्स सिटी की जमीन

नोएडा, एजेंसी। वित्तीय संकट से जूझ रहे जेपी ग्रुप की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। कंपनी पर यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण का 108 करोड़ रुपये का बकाया है।

प्राधिकरण ने कहा है कि इस साल के अंत तक बकाया नहीं चुकाया गया तो कंपनी से फॉर्मूला वन बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट और जेपी स्पोर्ट्स सिटी के लिए आवंटित 1,000 एकड़ भूमि वापस ली जा सकती है।

यमुना एक्सप्रेस वे पर टोल दरों को लेकर प्राधिकरण ने लिया ये बड़ा फैसला

प्राधिकरण के चेयरमैन प्रभात कुमार ने यहां पत्रकारों से कहा कि प्राधिकरण के निदेशक मंडल ने जेपी ग्रुप को थोड़ी राहत देने का निर्णय किया है। कंपनी को यह राशि सितंबर तक चुकानी थी।

अब उसे एक माह का और समय दिया गया है ताकि वह अपना सारा कर्ज निपटा सके। अन्यथा उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है, जिसमें भूमि का आवंटन निरस्त किया जा सकता है।

कंपनी को कई बार दिया गया समय

प्राधिकरण के निदेशक मंडल ने मंगलवार को यहां बैठक कर यह निर्णय किया। कुमार ने कहा कि 1,000 एकड़ भूमि आवंटन के बदले जेपी ग्रुप पर प्राधिकरण का 108 करोड़ रुपये बकाया है। यह भूमि फॉर्मूला वन बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट और जेपी स्पोर्ट्स सिटी के निर्माण के लिए दी गई थी। प्राधिकरण ने इस भुगतान के लिए कंपनी को कई बार समय दिया, लेकिन वह इसकी किस्तों का भुगतान करने में असफल रही। निपटान करे अन्यथा कार्रवाई के लिए तैयार रहे।

होटल और पेट्रोल पंप खोलने को मंजूरी

जेपी ग्रुप की दो कंपनियां जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड और जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड दिवाला एवं शोधन अक्षमता प्रक्रिया का सामना कर रही हैं। प्राधिकरण की 64वीं निदेशक मंडल की बैठक में यमुना एक्सप्रेस-वे पर चुंगी नहीं बढ़ाने का भी निर्णय किया गया। साथ ही एक्सप्रेस वे से लगे सेक्टर 18, 20 और 29 में 12 होटल और सात पेट्रोल पंप खोलने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई।

बंद डिब्बों में बिक रही उत्तराखंड के पहाड़ों की हवा, दिल्ली से लेकर यूपी तक मांग

हल्द्वानी। उत्तराखंड के हिमालयी बुग्यालों की शुद्ध हवा भी बिकने लगी है। हिमालयन फ्रेश एयर से भरे डिब्बे ऑनलाइन बिक रहे हैं। दस लीटर हवा के एक डिब्बे की कीमत करीब 800 रुपये है। वहीं छूट के साथ यह डिब्बा 550 रुपये में मिल रहा है। एक पैकिंग से 160 बार हिमालय की शुद्ध हवा ली जा सकती है। प्रदूषण की मार झेल रहे दिल्ली-एनसीआर में शुद्ध हवा के डिब्बों की काफी मांग है। प्योर हिमालयन एयर नाम की वेबसाइट अपने डिब्बों में उत्तराखंड की हवा बेच रही है। उत्तराखंड के हिमालयी इलाकों से हवा को कंप्रेस कर खास किस्म की पैकिंग में भरा गया है। डिब्बे पर दर्ज जानकारी में कंपनी दावा करती है कि हवा उत्तराखंड के चमोली जिले के रूपकुंड और बागेश्वर जिले से लगते पिंडारी क्षेत्र से डिब्बाबंद की गई है। कंपनी ने अपनी वेबसाइट पर कोई स्थायी पता या फोन नंबर नहीं दिया है। केवल ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट से ही इसकी डिलिवरी दे रही है।

दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक मांग

दिल्ली, एनसीआर का इलाका प्रदूषण से सबसे अधिक जूझ रहा है। यही कारण है कि डिब्बों में बंद शुद्ध हवा की इन्हीं इलाकों में सबसे अधिक मांग है। देश के सबसे प्रदूषित शहरों में दिल्ली के बाद उत्तरप्रदेश के छह शहरों का नंबर आता है।

चिंताजनक : भारत सबसे अधिक झेल रहा जलवायु परिवर्तन की मार

लोगों को पसंद आ रहा

लोगों को शुद्ध हवा बेचने का यह तरीका काफी पसंद आ रहा है। वे इसे प्रदूषण से निपटने में सहायक करार दे रहे हैं।

यमुना एक्सप्रेस वे पर टोल दरों को लेकर प्राधिकरण ने लिया ये बड़ा फैसला

ग्रेटर नोएडा, एजेंसी। यमुना एक्सप्रेस वे पर सात पैसे प्रति किलोमीटर टोल दर बढ़ाने का प्रस्ताव प्राधिकरण के बोर्ड ने खारिज कर दिया। प्राधिकरण ने कहा कि पहले एक्सप्रेस वे पर सुरक्षा मानक दुरुस्त किए जाएं। इसके बाद टोल दर बढ़ाने पर विचार होगा। जून 2016 से टोल दरें नहीं बढ़ाई गई हैं। जेपी ग्रुप ने यमुना एक्सप्रेस वे पर टोल दरें बढ़ाने का प्रस्ताव यमुना प्राधिकरण को दिया था। यमुना प्राधिकरण के बोर्ड ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। पिछले साल भी टोल दर बढ़ाने का प्रस्ताव आया था। उस समय प्राधिकरण ने शर्त रखी थी कि बढ़ी दर का जो पैसा आएगा उसको संयुक्त खाते में रखा जाए और पैसा एक्सप्रेस वे सुरक्षा प्रबंधों पर खर्च किया जाए लेकिन यह काम यमुना एक्सप्रेस वे प्रबंधन ने नहीं किया। प्राधिकरण बोर्ड ने इसी आधार पर यह प्रस्ताव खारिज कर दिया।

जेवर एयरपोर्ट की स्टेटस रिपोर्ट रखी :

बोर्ड बैठक में जेवर एयरपोर्ट की स्टेटस रिपोर्ट भी रखी गई। इसमें अब तक की प्रगति को बताया गया। प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग एंड इंप्लीमेशन कमेटी ने बिड डाक्यूमेंट और निर्माण कंपनी के साथ होने वाले एग्रीमेंट को पास कर दिया है।

जेपी ग्रुप भुगतान करे

प्राधिकरण ने जेपी ग्रुप को रिशेडयूलमेंट में प्लॉट दिया था। इसमें जेपी को 108 करोड़ रुपये जमा करने थे लेकिन अभी तक नहीं जमा किया है। बोर्ड ने कहा कि अगर जेपी ग्रुप 31 दिसंबर तक पैसा नहीं दिया तो कार्रवाई की जाएगी। उधर प्राधिकरण ने सेफ्टी ऑडिट के लिए राइट्स एजेंसी को रखा था। एक्सप्रेस वे पर पहले सुरक्षा मानक दुरुस्त किए जाएं। इसके बाद टोल दर बढ़ाने पर विचार होगा। सुप्रीम कोर्ट भी हाइवे पर हादसे रोकने के लिए चिंता जता चुका है। इसको लेकर राज्य सरकार ने कमेटी बनाई हुई है। कमेटी ने यहां पर कई काम करने के लिए कहा है। -डॉ. अरुणवीर सिंह, यमुना प्राधिकरण के सीईओ

बिल्डरों को भूमि 40% भुगतान पर ही मिलेगी

वहीं, यमुना प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में बिल्डरों को जमीन आवंटन को लेकर कई बदलाव किए हैं। अब बिल्डरों को 40 प्रतिशत पैसा जमा करने पर ग्रुप हाउसिंग, कॉमर्शियल और टाउनशिप के लिए जमीन आवंटित की जाएगी। उनको आठ के बजाय पांच साल में पैसा जमा करना होगा। बिल्डर प्रोजेक्ट में अब शर्तों के साथ आशंकि पूर्णता प्रमाणपत्र जारी किए जा सकेंगे। इससे खरीदारों को भी राहत मिलेगी। यमुना प्राधिकरण में मंगलवार को बोर्ड की 64वीं बैठक चेयरमैन डॉ. प्रभात कुमार की अध्यक्षता में हुई। बैठक में सीईओ डॉ. अरुणवीर सिंह, डीएम बीएन सिंह भी शामिल हुए। बोर्ड ने बिल्डरों को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। अभी तक ग्रुप हाउसिंग, कॉमर्शियल और टाउनशिप के लिए 30 प्रतिशत पैसा जमा करने पर जमीन आवंटित कर दी जाती थी लेकिन अब इसमें 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। 10 प्रतिशत रजिस्ट्रेशन शुल्क और 30 प्रतिशत आवंटन राशि जमा करने के बाद ही जमीन पर कब्जा मिल सकेगा। बाकी पैसा अभी तक आठ वर्षों में देना होता था। अब पांच साल में यह पैसा छमाही किस्तों में देना होगा। अब हर तरह के आवंटियों को पांच साल में ही पैसा जमा करना होगा। इस पर प्राधिकरण ने मुहर लगा दी। यमुना प्राधिकरण प्रोजेक्ट पूरा होने पर ही पूर्णता प्रमाणपत्र जारी करता है लेकिन अब प्राधिकरण ने नोएडा-ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की नीति का अपनाया है।

दखल

क्यों तबाही मचा रहे हैं चक्रवाती तूफान

भारत ही नहीं दुनियाभर में चक्रवाती तूफान समय-समय पर अपना रौद्ररूप दिखाते रहे हैं। भारत की तैयारी इनसे निपटने में अब तक नाकाम साबित होती रही है, लेकिन हाल ही में आए गाजा तूफान से निपटने में बचाव दल ने जो सक्रियता दिखाई, वह काबिलेतारीफ है। कुदरत के रहस्यों की ज्यादातर जानकारी अभी अधूरी है। आपदाओं को हम रोक नहीं सकते, लेकिन उनका सामना या असर कम करने की दिशा में बहुत कुछ कर सकते हैं।

ओडिशा में आए चक्रवाती तूफान तितली की आहट अभी धूमिल भी नहीं पड़ी थी कि तमिलनाडु में गाजा तूफान ने अपनी धमक दर्ज करा दी। इस चक्रवात की रफ्तार 120 किमी प्रति घंटा रही। इसके असर से तमिलनाडु के सात जिलों में भारी बारिश हुई, दो दर्जन से ज्यादा लोग मारे गए और आपदा प्रबंधन विभाग ने 81 हजार लोगों को तटीय इलाकों से हटाकर जान बचाई। राज्य में चलीं तूफानी हवाओं से हजारों पेड़ और बिजली के खंभे गिर गए। हजारों घर ध्वस्त हो गए और नमक की खेती बर्बाद हो गई। मौसम विभाग की सटीक भविष्यवाणी व आपदा प्रबंधन के समन्वित प्रयासों के चलते समुद्र तटीय रहवासियों के प्राण बचा लिए गए, अन्यथा बड़ी जनहानि हो सकती थी। इस परिप्रेक्ष्य में अन्य एजेंसियों ने आपदा से कुशलतापूर्वक सामना करके एक भरोसेमंद मिसाल पेश की है, जो सराहनीय एवं अनुकरणीय है। अलबत्ता अब चिंता की बात यह है कि इन चक्रवातों का सिलसिला क्यों निरंतर बन रहा हैं।

दरअसल बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने गहरे दबाव का क्षेत्र तीव्र होकर चक्रवाती तूफान गाजा में बदल गया था। इसके उठने का अनुमान लगाकर मौसम विभाग ने तमिलनाडु सरकार को कई स्थानों पर भयंकर बारिश और तेज हवाएं चलने की आशंकाएं जताई थी। भारतीय मौसम विभाग के अनुमान अकसर सही साबित नहीं होते, इसलिए उसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठते रहे हैं। लेकिन फेलिन, हुदहुद, तितली और गाजा चक्रवात से जुड़ी उसकी भविष्यवाणी सटीक बैठी हैं। इन अवसरों पर हमारे मौसम विज्ञानी सुपर कम्प्यूटर और डापलर रडार जैसी श्रेष्ठतम तकनीक के माध्यमों से चक्रवात के अनुमानित और वास्तविक रास्ते का मानचित्र एवं उसके भिन्न क्षेत्रों में प्रभाव के चित्र बनाने में भी सफल रहे हैं। तूफान की तीव्रता, हवा की गति व बारिश के अनुमान भी कमोबेश सही साबित हुए। इन अनुमानों को और कारगर बनाने की जरूरत है, जिससे बाढ़, सूखे, भूकंप और बवंडरों की पूर्व सूचनाएं मिल सकें और इनसे सामना किया जा सके। साथ ही मौसम विभाग को ऐसी निगरानी प्रणालियां भी विकसित करने की जरूरत है, जिनके मार्फत हर माह और हफ्ते में बरसात होने की राज्य व जिलेवार भविष्यवाणियां की जा सकें।

यदि ऐसा मुमकिन हो पाता है तो कृषि का बेहतर नियोजन संभव हो सकेगा। साथ ही अतिवृष्टि या फिर अनावृष्टि के संभावित परिणामों से कारगर ढंग से निपटा जा सकेगा। किसान भी बारिश के अनुपात में ही फसलें बोने लग जाएंगे। लिहाजा कम या ज्यादा बारिश का नुकसान उठाने से किसान मुक्त हो जाएंगे। मौसम संबंधी उपकरणों के गुणवत्ता व दूरंदेशी होने की इसलिए भी जरूरत है, क्योंकि जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से समुद्रतटीय इलाकों में आबादी भी ज्यादा है और वे आजीविका के लिए समुद्री जीवों पर निर्भर हैं। लिहाजा समुद्री तूफानों का सबसे ज्यादा संकट इसी आबादी को झेलना पड़ता है। यही कारण था कि 1999 में जब ओडिशा में नीलम (फैलिन) तूफान आया था तो हजारों लोग सटीक भविष्यवाणी न होने और आपदा प्रबंधन की कमी के चलते मारे गए थे। 12 अक्टूबर 2013 को उष्णकटिबंधीय चक्रवात फैलिन ने ओडिशा तट पर दस्तक दी थी। अंडमान सागर में कम दबाव के क्षेत्र के रूप में उत्पन्न हुए फैलिन ने नौ अक्टूबर को उत्तरी अंडमान-निकोबार द्वीप समूह पार करते ही एक चक्रवाती तूफान का रूप ले लिया था। इसने सबसे ज्यादा नुकसान ओडिशा और आंध्र प्रदेश में किया था। इस चक्रवात की भीषणता को देखते हुए छह लाख लोग सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाए गए थे। तूफान का केंद्र रहे गोपालपुर से तूफानी हवाएं 220 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से गुजरी थी।

साल 2004 में आए सुनामी तूफान का असर सबसे ज्यादा इन्हीं इलाकों में देखा गया था। हालांकि हिंद महासागर से उठे इस तूफान से 14 देश प्रभावित हुए थे। तमिलनाडु में भी इसका असर देखने में आया था। इससे मरने वालों की संख्या करीब दो लाख 30 हजार थी। भारत के इतिहास में इसे एक बड़ी प्राकृतिक आपदा के रूप में देखा जाता है। 8 और 12 अक्टूबर 2014 में आंध्र एवं ओडिशा में हुदहुद तूफान ने भी भयंकर कहर बरपाया था। इसकी दस्तक से इन दोनों राज्यों के लोग सहम गए थे। भारतीय नौसेना एनडीआरएफ ने करीब चार लाख लोगों को सुरक्षित क्षेत्रों में पहुंचाकर उनके प्राणों की रक्षा की थी। इसलिए इसकी चपेट से केवल छह लोगों की ही मौत हुई। हालांकि आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा तबाही 1839 में आए कोरिंगा तूफान ने मचाई थी। गोदावरी जिले के कोरिंगा घाट पर समुद्र की 40 फीट ऊंची उठी लहरों ने करीब तीन लाख लोगों को निगल लिया था। समुद्र में खड़े 20 हजार जहाज कहां विलीन हुए पता ही नहीं चला। 1789 में कोरिंगा से एक और समुद्री तूफान टकराया था, जिसमें लगभग 20 हजार लोग मारे गए थे।

कुदरत के रहस्यों की ज्यादातर जानकारी अभी अधूरी है। जाहिर है, चक्रवात जैसी आपदाओं को हम रोक नहीं सकते, लेकिन उनका सामना या उनके असर कम करने की दिशा में बहुत कुछ कर सकते हैं। भारत के तो तमाम इलाके वैसे भी बाढ़, सूखा, भूकंप और तूफानों के लिहाज से बेहद संवेदनशील हैं। जलवायु परिवर्तन और प्रदूषित होते जा रहे पर्यावरण के कारण ये खतरे और इनकी आवृत्ति लगातार बढ़ रही है। कहा यह भी जा रहा है कि फेलिन, ठाणे, आइला, आईरिन, नीलम और सैंडी जैसी आपदाएं प्रकृति की बजाय आधुनिक मनुष्य और उसकी प्रकृति विरोधी विकास नीति का पर्याय हैं। गौरतलब है कि 2005 में कैटरीना तूफान के समय अमेरिकी मौसम विभाग ने इस प्रकार के प्रलयंकारी तूफान 2080 तक आने की आशंका जताई थी, लेकिन वह सैंडी व नीलम तूफानों के रूप में 2012 में ही आ धमके। 17 साल पहले ओडिशा में सुनामी से फूटी तबाही के बाद यह तथ्य रेखांकित किया गया था कि अगर मैग्रोंव वन बचे रहते तो तबाही कम होती। दरअसल, जंगल एवं पहाड़ प्राणी जगत के लिए सुरक्षा कवच हैं, इनके विनाश को यदि नीतियों में बदलाव लाकर नहीं रोका गया तो तय है कि आपदाओं के सिलसिलों को भी रोक पाना मुश्किल होगा? लिहाजा नदियों के किनारे अवासीय बस्तियों पर रोक और समुद्र तटीय इलाकों में मैंग्रोव के जंगलों का संरक्षण जरूरी है।

दरअसल कार्बन फैलाने वाली विकास नीतियों को बढ़ावा देने के कारण धरती के तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है। यही कारण है कि बीते 134 सालों में रिकार्ड किए गए तापमान के जो 13 सबसे गर्म वर्ष रहे हैं, वे 2000 के बाद के ही हैं और आपदाओं की आवृत्ति भी इसी कालखंड में सबसे ज्यादा बढ़ी हैं। पिछले तीन दशकों में गर्म हवाओं का मिजाज तेजस्वी लपटों में बदला है। इसने धरती के 10 फीसदी हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया है। तापमान की वृद्धि का अनुमान लगा लिए जाने के आधार पर अंतर सरकारी पैनल ने भी भारतीय समुद्री इलाकों में चक्रवाती तूफानों की संख्या बढ़ने की आषंका जताई है। इस लिहाज से हमारी संस्थाओं की जो जवाबदेही, गाजा चक्रवात से सामना करने में दिखाई दी, उसकी निरंतरता बनी रहनी चाहिए। मौसम विभाग की भविष्यवाणी के बाद बचाव और राहत की तैयारी के लिए तीन दिन मिले थे। इन्हीं तीन दिनों में केंद्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण सक्रिय हो गया। इस तरह की तस्वीर भविष्य में इसलिए भ दिखनी जरूरी है, ताकि चक्रवात अपना रौद्र रूप न दिखा पाए।

प्रांजल भार्गव
(वरिष्ठ पत्रकार)

विचार

मतदान के महत्व को मानें हम

मध्यप्रदेश में कल यानी बुधवार को मतदान होगा। इस बार कुल पांच करोड़ से भी ज्यादा मतदाता नई सरकार के लिए वोट करेंगे। अत: यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम वोटिंग प्रतिशत को 2003 के मुकाबले ज्यादा से ज्यादा बढ़ाकर पूरे देश के सामने नजीर पेश करें।

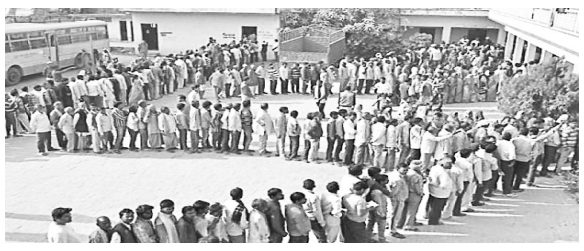

मध्यप्रदेश में नई विधानसभा के लिए कल यानी बुधवार को मतदान होगा। हमारे यहां चुनाव को लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। मध्यप्रदेश में भी इसी भाव को लेकर चुनाव आयोग ने तैयारी की है और हर मतदाता से अपना वोट देने की अपील की है। प्रदेश में कुल पांच करोड़ चार लाख 95 हजार मतदाता दो हजार 907 प्रत्याशियों में से अपना नेता चुनेंगे। इस बार भाजपा व कांग्रेस के बीच कांटे की लड़ाई है। कल एक लड़ाई हमें खुद से भी लड़नी है। मतदान के प्रति मन में वैराग्य या कुंठा को हावी नहीं होने देना है और सबसे पहले मतदान करना है। हमारा वोट न सिर्फ लोकतंत्र को मजबूती देता है, बल्कि मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था के प्रति सोच को भी प्रदर्शित करता है। नक्सली खतरे को मात देते हुए पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ ने हमारे सामने उम्दा उदाहरण पेश किया है। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस क्रम को आगे बढ़ाते रहें और मत प्रतिशत को 2003 के मुकाबले ज्यादा से ज्यादा बढ़ाकर पूरे देश के लोगों के सामने नजीर पेश करें।

कल मध्यप्रदेश तथा मिजोरम और उसके बाद सात दिसंबर को राजस्थान और तेलंगाना में मतदान होना है। इन चुनावों के बाद अगले साल लोकसभा के चुनाव भी संभावित हैं। मतदान का गिरता प्रतिशत क्या यह सवाल नहीं उठा रहा है कि देश में मताधिकार को मताधिकार के कर्तव्य में बदल देना चाहिए? इस विचार के पीछे कारण है मतदान का गिरता हुआ प्रतिशत। हम कई चुनावों में 60 फीसदी का आंकड़ा भी नहीं पार कर पाए हैं। कभी-कभी कुछ चुनाव क्षेत्रों में मतदान 25-35 प्रतिशत भी देखा गया है। 14-15 प्रतिशत वोट लेकर भी उम्मीदवार जीत जाते हैं। यह लोकतंत्र की सही अभिव्यक्ति नहीं है। कम मतदान होने से संसदीय लोकतंत्र का उद्देश्य पूरा नहीं होता। यह भी देखा जाता है कि ग्रामीण जनता और समाज का गरीब तबका तो काफी उत्साह से मतदान में भाग लेता है, लेकिन पढ़े-लिखे और संपन्न लोग ज्यादा महत्व नहीं देते, जबकि सरकार की आलोचना में वे सबसे मुखर होते हैं। इसीलिए यह सवाल उठ रहा है कि क्या मतदान को अनिवार्य नहीं किया जा सकता?

मध्यप्रदेश के पिछले चुनाव में वोटिंग का प्रतिशत 72.52 जरूर था, मगर इससे संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता। लिहाजा इस बार इस आंकड़े में और बढ़ोतरी करनी होगी। पिछले चुनाव में पुरुषों के मुकाबले महिला मतदाताओं की संख्या काफी कम थी। इस बार महिलाओं के सामने यह चुनौती होगी कि वे पुरुषों से ज्यादा मतदान केंद्रों तक आएं। देश में बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है जो अपने मताधिकार को लेकर उदासीन रहते हैं और यदा-कदा मतदान करने घर से निकलते भी हैं तो मतदान केंद्रों पर लगी लंबी कतार को देखकर बगैर वोट डाले ही घर लौट जाते हैं। ऐसे में क्या हम स्कूली शिक्षा के जरिए ही बच्चों में मतदान के महत्व का संस्कार नहीं डाल सकते ताकि वे वयस्क होने पर खुद ही अपने मताधिकार के प्रति जागरूक रहें।

ट्रांसजेंडर्स का इंसानी हक

भारतीय समाज में किन्नर स्त्रियों की अपेक्षा और भी ज्यादा हाशिए पर हैं क्योंकि उनके सामने अभी तक अपनी पहचान और सम्मान का ही संकट है। इस तबके के लिए राजनीति में हाथ आजमाना और भी बड़ी बात है। सालों पहले पंचायत के चुनावों में पहली बार जीतकर आई स्त्रियों की जो स्थिति थी, कुछ वैसी ही स्थिति आज किन्नरों की है। मगर आज वे खुद अपनी स्थिति बदल रही है। हमें भी सहयोग देना होगा।

हाल ही में छत्तीसगढ़ की वीणा सेंद्रे ने देश की पहली ट्रांस ब्यूटी क्वीन का खिताब जीता है। इस अहम प्रतियोगिता में अलग-अलग राज्यों से ट्रांसजेडर्स शामिल हुई थीं। ब्यूटी कॉन्टेस्ट पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित किया गया। ट्रांसजेंडर्स समुदाय को संवैधानिक मान्यता मिलने के बाद से इस स्पर्धा का दायरा बढ़ा है। कुछ समय पहले केरल में ट्रांसजेंडरों के लिए जी-टैक्सी सर्विस शुरू की गई है जिसमें टैक्सी के मालिक ट्रांसजेंडर ही होंगे और इसे चलाने का जिम्मा भी उनका होगा। इससे पहले चेन्नई की रहने वाली वीके पृथिका देश की पहली ट्रांसजेंडर पुलिस सब-इंस्पेक्टर बनी थीं। गौरतलब है कि पहले पृथिका का आवेदन खारिज कर दिया गया था, क्योंकि पुलिस भर्ती बोर्ड के पास तीसरे लिंग के लिए कोई श्रेणी नहीं थी। ऐसे में मद्रास हाईकोर्ट ने भर्ती बोर्ड को यह निर्देश दिया था कि वह भर्ती के नियमों में बदलाव करे, ताकि राज्य पुलिस बल में ट्रांसजेंडरों की भर्ती की जा सके। याद होगा कि पिछले साल गंगा कुमारी को राजस्थान पुलिस विभाग में पहली ट्रांसजेंडर महिला कांस्टेबल की नौकरी मिली है। हाल ही में सत्य श्री शर्मिला देश की पहली ट्रांसजेंडर वकील बनी हैं और बीते साल जोयिता मंडल देश की पहली ट्रांसजेंडर जज बनी थीं।

हालिया समय में देश में ऐसे कई सुखद उदाहरण सामने आए हैं, जो बताते हैं कि ट्रांसजेंडर्स समाज की मुख्यधारा में सम्मान व अधिकार हासिल करने के लिए अपने बलबूते अपनी पहचान बना रहे हैं। सुखद है कि इस समुदाय के लोग अब बढ़-चढ़कर हर क्षेत्र में अपनी मौजूदगी दर्ज करवाने में सफल हैं। थर्ड जेंडर को कानून से जो बराबरी का हक मिला है उसे धीर-धीरे ही सही मगर सामाजिक स्वीकार्यता मिल रही है। यह रेखांकित किए जाने योग्य बदलाव है कि अनगिनत बाधाओं और भेदभावों के बावजूद थर्ड जेंडर के लोग हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि ट्रांसजेंडर्स के मानवीय अधिकारों को लेकर भारत ही नहीं दुनियाभर में लंबे समय से बहस जारी है। भारत में 2014 में ही एक ऐतिहासिक और मानवीय फैसले में भारतीय उच्चतम न्यायालय थर्ड जेंडर को तीसरी लिंग श्रेणी की मान्यता दी थी। मनुष्यता का मान करने वाले इस फैसले के बाद भारत भी दुनिया के ऐसे इक्के-दुक्के देशों में शामिल हो गया है, जहां पर ट्रांसजेंडर्स को यह दर्जा मिला हुआ है।

शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे बुनियादी अधिकारों से भी वंचित इस तबके लिए यह निर्णय यकीनन मानवीय गरिमा की प्रतिष्ठा करने वाला ही था। उच्चतम न्यायालय ने ट्रांसजेंडर्स को शिक्षण संस्थाओं और नौकरियों में आरक्षण देने की भी बात कही थी। इस फैसले बाद उन्हें शिक्षा, सामाजिक समानता और काम पाने का पूरा अधिकार है। इसे फैसले को ट्रांसजेंडर वर्ग के लिए समानता और सम्मान को बढ़ावा देने वाली सोच को आगे ले जाने वाली कड़ी के रूप में देखा गया। जिसका असर अब दिख भी रहा है। दरअसल, थर्ड जेंडर के साथ होने वाले भेदभाव पूर्ण व्यवहार को दूर करने के लिए उन्हें काम पाने का समान अधिकार मिलना जरूरी है। पृथिका के मामले में मद्रास हाईकोर्ट के आदेश ने इस बात को सिद्ध किया था कि समाज में हर मनुष्य को अपने जीवन को पूरा जीने का अधिकार है। फिर चाहे वो महिला हो पुरुष हो या थर्ड जेंडर। ऐसे में बात चाहे ब्यूटी क्वीन का खिताब जीतने की हो या किसी अन्य क्षेत्र में काम पाने की। सुखद है कि ट्रांसजेंडर्स के लिए मानवीय हक पाने की यह राह कुछ सहज होती दिख रही है।

गौरतलब है कि 2011 की जनगणना में इस समुदाय के लोगों की गिनती अन्य में की गई थी, जिसके आंकड़े जारी नहीं किए गए पर गैर सरकार संगठनों की माने तो किन्नरों की आबादी 5 लाख तक होने का अनुमान है। वैसे तो हमारे देश में संविधान के जरिए यह सुनिश्चित है कि धर्म, जाति या लिंग के आधार पर किसी के साथ कोई भी भेदभाव न हो। लेकिन समाज में हमेशा से हाशिये पर रहे ट्रांसजेंडर समुदाय की सामाजिक स्वीकार्यता को लेकर आज भी आमजन की मानसिकता में बड़ा बदलाव नहीं आया है। इस परिस्थिति में देश के इस तबके को सम्मानजनक ढंग से काम मिले तो सामाजिक सोच में भी बदलाव जरूर आएगा। ऐसा होना लाजिमी भी है क्योंकि अपनी काबिलियत के बल पर इस समुदाय के लोगों ने भी अपनी एक अलग पहचान बनाई है। हैदराबाद की शबनम मौसी देश की पहली ट्रांसजेंडर एमएलए बनकर एक मिसाल कायम कर चुकी हैं। ऐसे ही छत्तीसगढ़ की मधु किन्नर मेयर बन चुकी हैं। कुछ ही समय पहले एक और नाम सुर्खियों में आया जब थर्ड जेंडर समुदाय से आने वाली पद्मिनी प्रकाश ने अपनी प्रतिभा के बल पर न्यूज एंकर तक की नौकरी हासिल की थी। तमाम बाधाओं और असमानताओं के बावजूद थर्ड जेंडर के लोगों का यूं आगे आना वाकई सराहनीय है।

दरससल, समाज द्वारा थर्ड जेंडर के लोगों को हेय दृष्टि से देखा जाना ही उनको सबसे अधिक पीड़ा देता है। इसीलिए कानूनी फैसलों और आदेशों के साथ ही समग्र रूप से पूरे समाज की सोच में बदलाव आना भी जरूरी है। हर क्षेत्र में उनकी स्वीकार्यता का भाव अति आवश्यक है। असल मायने में देखा जाए तो यह सामाजिक स्वीकार्यता का भाव ही थर्ड जेंडर की कानूनी मान्यता को मानवीय आधार दे सकता है, जबकि आज भी पहले की ही तरह ट्रांसजेंडर्स की सामाजिक उपेक्षा बरकरार है। उनके प्रति समाज के सभी वर्गों का असहयोगी और अशोभनीय व्यवहार यदाकदा देखने को मिलता है। ऐसे में जरूरी है कि समाज के इस वर्ग को भी सामाजिक परिवेश से लेकर कार्यस्थल तक, मान और अधिकार मिलें। समाज के हाशिये पर पड़े इस तबके को भी मानवीय गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार है। इसके लिए क्षमता और योग्यता के मुताबिक काम पाने का सहज माहौल मिलना ही चाहिए। यकीनन, प्रशासनिक सक्रियता और सामाजिक व्यवहार का परिवर्तन ट्रांसजेंडर्स का सम्मान और अधिकार दोनों बनाए रख सकता है। जिस हिम्मत के साथ इस समुदाय से कई चेहरे आगे आ रहे हैं, उनके मनोबल को बनाए रखने के लिए इतना करना समाज की नैतिक जिम्मेदारी भी है।

पिछले दिनों तमिलनाडु की यात्रा के दौरान भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने अप्सरा रेड्डी नाम के एक किन्नर को अपनी पार्टी में शामिल किया। अमित शाह के इस कदम के बाद ही एक अन्य किन्नर को कांग्रेस पार्टी की तरफ से पार्टी में शामिल होने का निमंत्रण मिला। सदियों से उपेक्षित किन्नर समुदाय को मुख्यधारा में लाने के लिए तमिलनाडु में काफी समय से कोशिशें होती रही हैं। वह भारत का पहला राज्य है जहां किन्नर कल्याणकारी बोर्ड बनाया गया है। इस बोर्ड में किन्नर प्रतिनिधि भी हैं। राज्य में किन्नरों के लिए शिक्षा और चिकित्सा क्षेत्र से लेकर नौकरी तक में कई कल्याणकारी योजनाएं हैं। अब कई स्थानीय और राष्ट्रीय पार्टियों द्वारा किन्नरों तक पहुंच बनाने की कवायद को इस दिशा में आगे के प्रयासों की तरह देखा जा सकता है, लेकिन पार्टियां किन्नरों को सिर्फ सौभाग्यसूचक समझकर अपना रही हैं या फिर वे इस तीसरे जेंडर के प्रति सच में सामाजिक जिम्मेदारी समझ रही हैं। यह सवाल है।

भारतीय समाज में किन्नर स्त्रियों की अपेक्षा और भी ज्यादा हाशिए पर हैं क्योंकि उनके सामने अभी तक अपनी पहचान और सम्मान का ही संकट है। इस तबके के लिए राजनीति में हाथ आजमाना और भी बड़ी बात है। सालों पहले पंचायत के चुनावों में पहली बार जीतकर आई स्त्रियों की जो स्थिति थी, कुछ वैसी ही स्थिति आज किन्नरों की है। जानकार यह मानते हैं कि इनमें से कुछ का फायदा उठाया जाएगा, कुछ पर निर्णय थोपे जाएंगे और कुछ लड़-झगड़कर निर्णय लेने की स्थिति में पहुंचेंगे। किन्नरों के लिए जमीनी स्तर पर काम करना चुनौती है।

डॉ. मोनिका शर्मा
(वरिष्ठ पत्रकार)

ट्विटर

मतदान का महत्व हम सभी को पता है, मगर मौजूदा राजनीतिक हालात में हम कुंठित हो गए हैं। इसलिए मतदान केंद्र तक जाने से बचते हैं। पर यह कोई स्थाई उपाय नहीं है।

विजय विद्रोही, वरिष्ठ पत्रकार

मतदान के जरिए लोकतंत्र मजबूत होता है। इसलिए यह हम सभी की की जिम्मेदारी है कि कर्तव्य से भागे नहीं। जब तक हम अपनी राय नहीं रखेंगे, बदलाव मुमकिन नहीं है।

एके जोती, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त

सत्यार्थ

सफलता पाने का उपाय

एक बार एक व्यक्ति स्वेट मार्डेन के पास आया और बोला- सर, मैं काम करने की इच्छा रखता हूं, लक्ष्य मैंने निर्धारित कर लिया है व जरूरी साधन भी मेरे पास हैं। इन सबके बाद भी न जाने क्यों मुझे मेरे कार्य में पूरी सफलता नहीं मिलती। यदि मैं काम न करूं तो विफल होने की बात मेरी समझ में आती है, लेकिन काम करते रहने पर भी विफल होते रहने की बात मेरी समझ से परे है। स्वेट मार्डेन बोले- तुम्हारे इस प्रश्न का जवाब बेहद सरल है। फिर भी मैं तुम्हें इसका जवाब एक उदाहरण के जरिए समझाता हूं। वह तुम आसानी से समझ भी जाओगे।

बहुत से लोग इस दुनिया में ऐसे हैं, जो कि अपने जीवन की गाड़ी को गुनगुने पानी से चलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे यह नहीं जानते कि पानी को जब तक 212 डिग्री तक गरम न किया जाए, उसमें भाप नहीं बनती है और जब तक पानी में भाप न बने, तब तक इंजन गाड़ी को खींच ही नहीं सकता है। यह उदाहरण सुनकर वह व्यक्ति बोला -इंजन का मेरे काम से क्या संबंध? स्वेट मार्डेन बोले-भाई, बस यह समझ लो कि तुम्हारे काम में मंद उत्साह ठीक वैसा ही असर करता है, जैसा कि असर गुनगुने पानी का इंजन के बॉयलर पर होता है। जब तक पानी 212 डिग्री तक गरम नहीं हो जाता, तब तक उसमें इंजन को खींचने की शक्ति नहीं आती। इसी तरह जब तक तुम अपने काम में संपूर्ण आत्मशक्ति व एकाग्रता को नहीं लग जाते, तब तक सफलता तुमसे दूर ही रहेगी। सारे साधन उपलब्ध होने पर भी मंद गति से काम करने पर मंजिल को नहीं पाया जा सकता। उनकी बात से वह युवक प्रभावित हुआ। उसने उसी क्षण निश्चय किया कि अब वह अपने उत्साह को मंद नहीं होने देगा और वह हर हाल में सफलता पाकर रहेगा।

रेनू सैनी

सार समाचार

यूरोपीय संघ में बड़े पैमाने पर पूर्वाग्रह का सामना कर रहे हैं अश्वेत लोग

विएना। यूरोपीय संघ में अश्वेत लोगों को जीवन के कई हिस्सों में आज भी बड़े पैमाने पर और गहन पूर्वाग्रह का सामना करना पड़ता है। उन्हें नस्लीय उत्पीड़न और हमलों का सामना करना पड़ता है। बुधवार को एक रिपोर्ट में यह कहा गया। रिपोर्ट की प्रस्तावना में ईयू एजेंसी फॉर फंडामेंटल राइट्स के निदेशक माइकल ओफ्लाहर्टली ने कहा, '' पूरे यूरोपीय संघ में व्यक्ति की त्वचा के रंग पर आधारित नस्लवाद बड़ा संकट बना हुआ है।'' रिपोर्ट का शीर्षक है '' यूरोपीय संघ में अश्वेत होना'। यह फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन समेत यूरोपीय संघ के 12 देशों के 5,800 से ज्यादा लोगों के वर्ष 2015 और 2016 में लिए गए साक्षात्कारों पर आधारित है। इनमें से 30 फीसदी लोगों ने कहा कि सर्वे से पहले पांच वर्ष में उन्हें किसी न किसी मौके पर नस्लीय उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। पांच फीसदी ने हिंसक हमले का सामना किया। लेकिन ऐसे मामलों में 60 फीसदी से अधिक लोगों ने अधिकारियों को उक्त घटना की जानकारी नहीं दी। उनमें से कई का कहना था कि उन्हें ऐसा लगता था कि इस बारे में किसी को कुछ बताने से भी कुछ नहीं होने वाला, या उनमें से कई को पुलिस पर भी भरोसा नहीं था।

जनरल मोटर्स के संयंत्र बंद करने पर ट्रूडो, ट्रंप ने जाहिर की 'नाराजगी'

ओटावा। जनरल मोटर्स के अपने संयंत्रों को बंद करने के निर्णय पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो दोनों ने नाराजगी जतायी है। दोनों नेताओं ने मंगलवार को फोन पर इस संबंध में बातचीत की और अपनी नाखुशी जाहिर की। ट्रूडो के प्रवक्ता कैमरन अहमद ने कहा, ''दोनों नेताओं ने कनाडा और अमेरिका में जनरल मोटर्स के अपने संयंत्र बंद करने पर नाखुशी जाहिर की। दोनों ने ही इससे प्रभावित होने वाले कंपनी के कर्मचारियों, उनके परिवारों और समुदायों के बारे में अपनी चिंता व्यक्त की।' व्हाइट हाउस की ओर से इस बातचीत की पुष्टि की गई है। उसका भी कहना है कि दोनों नेताओं ने कंपनी के इस निर्णय पर अपनी चिंता व्यक्त की और इस संबंध में जी-20 समूह देशों की बैठक के दौरान अपनी योजनाओं पर भी विचार-विमर्श किया। इसी हफ्ते अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में होने वाले जी-20 शिखर सम्मेलन में दोनों नेताओं के मुलाकात करने की उम्मीद है।

खशोगी हत्याकांड- सऊदी अरब के अधिकारियों से पूछताछ करेंगे अमेरिकी सांसद

वाशिंगटन। पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या को लेकर सऊदी अरब को दिए गए जवाब से नाराज अमेरिकी सांसद बुधवार को शीर्ष सरकारी अधिकारियों से पूछताछ करेंगे। इसमें ये सुनिश्चित हो सकेगा कि कांग्रेस सऊदी अरब को इसकी सजा देने के लिए कितना आगे तक जा सकती है। सीनेट में बहुमत के नेता मिश मैककोनेल ने कहा कि इस मामले में अमेरिका की ओर से सऊदी अरब को एक अलग तरह के जवाब देने की जरूरत है जबकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उसे जिम्मेदार ठहराने को लेकर टालमटोल कर रहे हैं।

करतारपुर समारोह में बोले इमरान- भारत के साथ मजबूत और शिष्ट व्यवहार चाहता है पाक

करतारपुर (एजेंसी)।

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने बुधवार को कहा कि उनका देश भारत के साथ 'मजबूत' और 'शिष्ट' संबंध चाहता है तथा प्रतिबद्धता के साथ दोनों देश कश्मीर सहित सभी मुद्दों को हल कर सकते हैं। इमरान ने सीमा के दोनों ओर दो पवित्र गुरूद्वारों को जोड़ने के लिए एक ऐतिहासिक गलियारे का शिलान्यास किया।यह बहुप्रतीक्षित गलियारा पाकिस्तान के करतारपुर में गुरुद्वारा दरबार साहिब को भारत के गुरदासपुर जिले में स्थित डेरा बाबा नानक गुरुद्वारा को जोड़ेगा। इस गलियारे से भारतीय सिख श्रद्धालु गुरुद्वारा दरबार साहिब तक वीजा रहित यात्रा कर सकेंगे। माना जाता है कि करतारपुर में ही सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी ने अंतिम सांस ली थी।

करतारपुर साहिब पाकिस्तान में रावी नदी के पार स्थित है और डेरा बाबा नानक से करीब चार किलोमीटर दूर है। सिख गुरु ने 1522 में इस गुरुद्वारे की स्थापना की थी।इमरान ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा, ''हम भारत के साथ अपने संबंधों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इस कार्यक्रम में पाकिस्तानी सेना के प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा, सरकारी अधिकारी, केंद्रीय मंत्रियों हरसिमरत कौर बादल और हरदीप सिंह पुरी तथा विदेशी राजनयिक भी शामिल हुए। इमरान ने कहा, ''अगर कई युद्ध लड़ चुके फ्रांस और जर्मनी शांति के साथ रह सकते हैं तो भारत और पाकिस्तान क्यों नहीं रह सकते।''

उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और भारत उन अवसरों को नहीं समझ सकते जो खुदा ने उन्हें दिया है। उन्होंने कहा कि जब कभी वह भारत गए तो उन्हें बताया गया कि राजनेता एकजुट हैं, लेकिन सेना दोनों पक्षों के बीच मित्रता नहीं होने देगी। उन्होंने कहा, ''मैं आज कह रहा हूं कि हमारे नेता, हमारी सेना और अन्य सभी संस्थान एकमत हैं। हम आगे बढ़ना चाहते हैं, हम एक शिष्ट संबंध चाहते हैं। हमारे सामने सिर्फ एक समस्या है, कश्मीर। अगर आदमी चंद्रमा पर चल सकता है तो कौन सी समस्याएं हैं, हम जिनका हल नहीं कर सकते?''

इमरान ने कहा, ''मैं आपको आश्वासन देता हूं कि हम इस समस्या का हल कर सकते हैं। लेकिन दृढ़ संकल्प और बड़े सपनों की जरुरत है। कल्पना कीजिए कि एक बार व्यापार शुरू हो जाता है, हमारा रिश्ते सुधर जाते हैं तो दोनों देशों को कितना फायदा हो सकता है।' उन्होंने एक बार फिर कहा कि यदि मित्रता के लिए भारत एक कदम आगे बढ़ाएगा तो पाकिस्तान दो कदम बढ़ेगा।इमरान ने कहा कि ÷दोनों तरफ से गलतियां÷ हुई हैं लेकिन दोनों पक्षों को अतीत में नहीं रहना चाहिए।उन्होंने सिख समुदाय को आश्वासन दिया कि अगले वर्ष गुरु नानक देव की 550 वीं जयंती पर करतारपुर साहिब की सुविधाएं और बेहतर होंगी। भारत ने करीब 20 साल पहले पाकिस्तान को इस गलियारे का प्रस्ताव दिया था। पंजाब के कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने भी समारोह में भाग लिया और कहा कि काफी खून-खराब हो चुका है और गलियारा क्षेत्र में शांति बहाल करने के लिए एक बड़ा अवसर होगा। इस कार्यक्रम को हरसिमरत कौर ने भी संबोधित किया और कहा कि अगर बर्लिन की

दीवार गिर सकती है तो भारत और पाकिस्तान के बीच घृणा और अविश्वास भी समाप्त हो सकता है।भावुक हरसिमरत कौर ने कहा कि इस गलियारे से दोनों देशों में खुशी और शांति आएगी।

करतारपुर कॉरीडोर खुलने का मतलब ये नहीं कि दोनों देशों के बीच बातचीत शुरू हो जाएगी: सुषमा स्वराज

नई दिल्ली (एजेंसी)।

पाकिस्तान स्थित करतापुर कॉरीडोर के उद्घाटन समारोह से पहले विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने दो टूक लहजे में कहा है कि इसके खुलने का आशय ये नहीं है कि इस कारण दोनों देशों के बीच बातचीत शुरू हो जाएगी क्योंकि आतंक और बातचीत एक साथ नहीं हो सकते. उन्होंने यह भी कहा कि भारत सरकार करतारपुर कॉरीडोर शुरू करने के लिए कई वर्षों से कह रही थी लेकिन पाकिस्तान ने अब जाकर सकारात्मक रुख अपनाया है. सुषमा स्वराज का बयान उन चर्चाओं के बीच आया है जिनमें कहा जा रहा है कि पाकिस्तान सार्क शिखर सम्मेलन के लिए भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निमंत्रण भेज सकता है. सुषमा स्वराज के बयान से स्पष्ट है कि भारत इस तरह के किसी भी आमंत्रण को स्वीकार करने के मूड में नहीं है.

उधर पाकिस्तान के करतारपुर स्थित गुरुद्वारा दरबार साहिब को भारत के गुरदासपुर जिले में स्थित डेरा बाबा नानक से जोड़ने वाले बहुप्रतीक्षित गलियारे की नींव वहां के प्रधानमंत्री इमरान खान बुधवार को रखने जा रहे हैं. इससे भारतीय सिख श्रद्धालुओं को वीजा मुक्त आवाजाही की सुविधा मिल सकेगी. पाकिस्तान ने इस कार्यक्रम के लिए भारत के 25 पत्रकारों के समूह को आमंत्रित किया है. इसी कड़ी में कूटनीतिक गलियारे में चर्चा है कि करतारपुर कॉरीडोर के माध्यम से पाकिस्तान दोनों देशों के बीच रिश्तों में जमी बर्फ को पिघलाने के लिए कोशिश कर सकता है. इसी कड़ी में पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि वह सार्क शिखर सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र

मोदी को आमंत्रित करेंगे. द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने पहले ही पाकिस्तान के इस तरह के किसी 'दिखावे' को खारिज करते हुए कहा है कि पाकिस्तान एकतरफा फैसला लेते हुए इस तरह से किसी को 'आमंत्रित' नहीं कर सकता. उल्लेखनीय है कि 2016 से सार्क शिखर सम्मेलन का आयोजन दोनों देशों के तल्ख रिश्तों की पृष्ठभूमि में नहीं हो सका है.

इस संबंध में कहा जा रहा है कि सार्क शिखर सम्मेलन का आयोजन तभी हो सकता है जब सभी सदस्य देश इसके लिए सहमत हों. सम्मेलन के लिए सदस्यों के बीच तारीखें तय होने के बाद ही निमंत्रण भेजा जा सकता है. इस संबंध में द टाइम्स ऑफ इंडिया से एक सूत्र ने कहा, 'भारत सार्क शिखर सम्मेलन में विशेष आमंत्रित सदस्य नहीं है, जिस कारण पाकिस्तान इसको आमंत्रित कर सकता है. भारत सार्क प्रक्रिया का अहम अंग है...सभी सदस्य देशों की सहमति से ही सार्क सम्मेलन के लिए तारीखें तय हो सकती हैं. लेकिन ऐसा हुआ नहीं है.'

सूत्रों के मुताबिक करतारपुर कॉरीडोर के उद्घाटन के दौरान पाकिस्तान प्रधानमंत्री इमरान खान भारतीय पत्रकारों से बातचीत कर सकते हैं और उस क्रम में कूटनीतिक चतुराई दिखाने के लिए सार्क सम्मेलन के आयोजन का कार्ड उनकी तरफ से खेला जा सकता है.

सार्क सम्मेलन

उल्लेखनीय है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने 2014 में काठमांडू में आयोजित सार्क शिखर सम्मेलन में शिरकत की थी. 2016 में उरी में आर्मी कैंप पर हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने इसमें शिरकत करने से इनकार कर दिया. बांग्लादेश, भूटान और अफगानिस्तान ने भी इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया. उसके बाद से ही सार्क शिखर सम्मेलन का आयोजन नहीं हो सका है.

करतारपुर कॉरीडोर

उल्लेखनीय है कि पाकिस्तान में करतारपुर साहिब, रावी नदी के पार डेरा बाबा नानक से करीब चार किलोमीटर दूर है. सिख गुरू ने 1522 में इसे स्थापित किया था. पहला गुरुद्वारा, गुरुद्वारा करतारपुर साहिब यहां बनाया गया था जहां माना जाता है कि गुरू नानक देव जी ने अंतिम दिन बिताए थे. पाकिस्तानी विदेश कार्यालय के प्रवक्ता मोहम्मद फैसल ने मंगलवार को कहा कि करतारपुर गलियारे के छह महीने में पूरा होने की उम्मीद है. यह कदम अगले साल गुरू नानक जी की 550वीं जयंती से पहले उठाया गया है. भारत ने भी कहा है कि वह गुरदासपुर जिले में डेरा बाबा नानक से अंतरराष्ट्रीय सीमा तक एक गलियारा विकसित करेगा जिससे गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर जाने वाले सिख श्रद्धालुओं को सुविधा मिल सके.

यूक्रेन-रूस संघर्ष के बाद पुतिन के साथ मुलाकात रद्द हो सकती है: ट्रंप

कीव (एजेंसी)।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह रूस और यूक्रेन के बीच समुद्र में संघर्ष के बाद रूस के अपने समकक्ष व्लादिमीर पुतिन के साथ लंबे समय से प्रतीक्षित सम्मेलन रद्द कर सकते हैं। इस संघर्ष के चलते कीव को ''पूर्ण युद्ध'' की धमकी देनी पड़ी। ट्रंप का इस सप्ताह के अंत में ब्यूनस आयर्स में जी-20 सम्मेलन में पुतिन से मुलाकात करने का कार्यक्रम है लेकिन उन्होंने चेतावनी दी कि यह यूक्रेन के तीन जहाजों को कब्जे में लेने के रूस के कदम पर उनके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की रिपोर्ट पर निर्भर करेगा। उन्होंने मंगलवार को 'द वाशिंगटन पोस्ट' से कहा, ''शायद, मैं मुलाकात ना करुं। शायद मेरी मुलाकात ना हो।'' इससे पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति पेत्रो पोरोशेंको ने चेतावनी दी कि पूर्व सोवियत पड़ोसियों के बीच तनाव बढ़ने से यह तनातनी और अधिक नाटकीय मोड़ ले सकती है। उन्होंने कहा, ''मैं नहीं चाहता कि कोई सोचे कि यह मजाक है और खेल है। यूक्रेन पर रूस के साथ पूर्ण युद्ध का खतरा है।'' रूस की सेना ने रविवार को क्रीमिया के तट पर यूक्रेन के तीन जहाजों को जब्त कर लिया और 24 यूक्रेनी नाविकों को बंधक बना लिया। इसके बाद ट्रंप ने यह बात कही। अमेरिका के विदेश विभाग ने रूस के कदम को तनाव में खतरनाक वृद्धि करने वाला बताया और कहा कि वाशिंगटन ''अपने यूरोपीय सहयोगियों को यूक्रेन की मदद के लिए और अधिक प्रयास करते हुए'' देखना चाहता है।

मानवाधिकार पर बैठक बुलाने के अमेरिकी प्रस्ताव का उत्तर कोरिया ने किया विरोध

संयुक्त राष्ट्र (एजेंसी)।

उत्तर कोरिया ने खुद के मानवाधिकार रिकॉर्ड पर चर्चा के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाने के अमेरिका के अनुरोध का विरोध किया है. उसने सुरक्षा परिषद के सदस्यों से जोर देकर इस बैठक को रोकने लिए कहा है.

उत्तर कोरिया का मानना है कि इससे शांति के लिए उठाए गए हालिया कदमों को नुकसान होगा. संयुक्त राष्ट्र में उत्तर कोरिया के राजदूत किम सोंग ने परिषद को मंगलवार को भेजे अपने पत्र में हैरानी और अफसोस जताते हुए कहा कि 10 दिसंबर को बैठक का आयोजन मौजूदा दौर के खिलाफ होगी.

अगर अमेरिका का प्रस्ताव माना गया तो यह उत्तर कोरिया में मानवाधिकार उल्लंघन को लेकर सुरक्षा परिषद की 5वीं सालाना बैठक होगी. अमेरिका 2014 से हर साल चीन के विरोध के बावजूद बैठक के लिए जरूरी 9 वोट जुटाता आया है. हर साल चीन ये कहकर इसका विरोध करता रहा है कि मानवाधिकारों पर चर्चा सुरक्षा परिषद नहीं बल्कि जेनेवा स्थित मानवाधिकार परिषद में होनी चाहिए.

उत्तर कोरिया के राजदूत ने अपने पत्र में लिखा कि इस बैठक से मौजूदा सकारात्मक माहौल को बढ़ावा देने के बजाय तनाव बढ़ेगा. उन्होंने उत्तर कोरिया में मानवाधिकार उल्लंघन को लेकर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख मिशेल बेशलेट को सुरक्षा परिषद में संबोधन के लिए बुलाने के अमेरिका के निमंत्रण को साजिश करार दिया.

नौका से भाग रहे 93 रोहिंग्या को वापस म्यामां शिविरों में भेजा गया : पुलिस

संयुक्त राष्ट्र (एजेंसी)।

यांगून। म्यामां से पलायन की कोशिश कर रहे करीब 100 रोहिंग्या मुस्लिमों को वापस रखाइन प्रांत भेज दिया गया है। उन्हें मलेशिया जाने वाले समुद्री मार्ग पर हिरासत में लिया गया। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी। इस घटना से एक बार फिर शरणार्थी नौका संकट गहराने के आसार बढ़ गये हैं।

पलायन कर रहे रोहिंग्या तीन नौकाओं में सवार थे। हालांकि नौकाएं अब जब्त कर ली गयी हैं और पिछले दो सप्ताह में उन्हें वापस रखाइन प्रांत भेज दिया गया है। मॉनसूनी मौसम के कारण समुद्र में जाने के लिये अनुकूल परिस्थिति है हालांकि नौका वहन में अब भी जोखिम बना है।

तीसरी नौका पर सवार सभी लोगों को सितवे के आस-पास के शिविरों में वापस भेजा जा रहा है। म्यामां में 2012 में हुई सांप्रदायिक हिंसा के बाद यहां 1,20,000 से अधिक लोग रह रहे हैं। स्थानीय मीडिया में जारी एक तस्वीर में चिलचिलानी धूप में नौका में सवार लोगों का समूह दिख रहा है जो 2015 के नौका संकट की याद दिलाती है।

पुलिस मेजर मिन त्लीन ने बताया कि रविवार रात दक्षिणी दवेई शहर के तट पर नौसेना के अधिकारियों ने जब उन्हें रोका, उस वक्त वे मलेशिया जा रहे थे। उन्होंने बताया, ''सभी को बीती रात नौसेना की एक नौका से सितवे भेज दिया गया।''।

2 साल से अधिक समय तक जेल में रहने पर चुनाव नहीं लड़ सकते: बांग्लादेशी अदालत

ढाका (एजेंसी)।

बांग्लादेश की एक अदालत ने गुरुवार अपने फैसले में कहा कि जो लोग अपनी लंबित याचिकाओं के साथ दो वर्षों से अधिक समय से जेल में बंद हैं, वे 30 दिसंबर को होने वाला आम चुनाव नहीं लड़ सकते. बीडीन्यूज24 की रिपोर्ट के अनुसार, यह आदेश विपक्षी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के पांच नेताओं अमानुल्लाह अमान, ए.जेड.एम. जाहिद हुसैन, वदूद भुईयां, मोहम्मद मोशीउर रहमान और मोहम्मद अब्दुल वहाब की गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका के संबंध में दिया गया है. अदालत ने कहा कि संविधान के अनुसार, अगर किसी व्यक्ति को जेल में दो वर्षों से ज्यादा समय तक रहने की सजा दी जाती है तो जबतक अपीलीय डिवीजन सजा को खारिज या निलंबित नहीं करता, वह चुनावों में भाग नहीं ले सकता/सकती है.

इस आदेश के बाद बीएनपी की अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया आगामी चुनाव नहीं लड़ सकेंगी, क्योंकि उन्हें भ्रष्टाचार के दो मामलों में 17 वर्ष की जेल की सजा सुनाई गई है.

बांग्लादेश की एक अदालत ने जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया को अगले महीने होने वाले आम चुनावों में भाग लेने से रोक दिया है. अदालत ने कहा कि दो साल से ज्यादा कैद की सजा पाये व्यक्ति चुनाव में शामिल नहीं हो सकते. अटॉर्नी जनरल महबूबे आलम ने कहा कि घूस के दो मामलों में दोषी ठहराई गईं बीएनपी अध्यक्ष जिया 30 दिसंबर को होने वाले 11वें आम चुनावों में हिस्सा नहीं ले सकतीं. पूर्व प्रधानमंत्री फिलहाल अपने दिवंगत पति जियाउर रहमान के नाम पर शुरू किये गए धर्मार्थ कार्यों से जूड़े घूस के दो मामलों में जेल की सजा काट रही हैं. हाईकोर्ट द्वारा यह कहे जाने के बाद कि दो साल से ज्यादा की कैद की सजा पाए व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकते भले ही सजा के खिलाफ उनकी याचिका अदालतों में लंबित हो.

इसके बाद एक संवाददाता सम्मेलन में आलम ने कहा, ''वह आगामी चुनाव में हिस्सा लेने के लिये अयोग्य हैं.'' वह आठ फरवरी से ही हिरासत में हैं जब ढाका की विशेष अदालत ने जिया अनाथालय ट्रस्ट घूस मामले में उन्हें दोषी ठहराते हुए पांच साल कैद की सजा सुनाई थी. 30 अक्टूबर को उच्च न्यायालय ने उनकी जेल की सजा को दोगुना करते हुए उसे 10 वर्ष कर दिया. एक सुनवाई अदालत ने 29 अक्टूबर को जिया धर्मार्थ ट्रस्ट घूस मामले में उन्हें दोषी ठहराते हुए सात साल की कैद और 10 लाख बांग्लादेशी टका के जुर्माने की सजा सुनाई थी.

संगम प्रिन्ट प्रा. लि. के कॉन्ट्रेक्टर को तीन महिने से हिसाब ने मिलने से परेशन होकर ट्रेन के निचे आकर दी जान

सूरत। बुधवार की दोपहर में मो. सरीफ ने सचिन मुल्ला डाईंग ओवर ब्रिज के निचे रेल्वे ट्रेक से जा रही ट्रेन के निचे आगर अपनी जीवन लीला समाप्ता कर ली। मो. सरीफ ने खुदखुशी करने से पहले अपने घर पर सुशाईड नोट भी छोड़ा जिसमें उसने संगम प्रिन्ट प्रा. लिं. सचिन जी.आई.डी.सी के मालिकों पर आरोप लगाया की उसके काम का हिसाब तीन महिने से ना देने के कारण उसके कारिगर उस पर बार-बार पैसे देन का दबाव बना रहे थे जिससे परेशान होकर बुधवार को में आत्म हत्या करने जा रहा हुं। जिसके बाद रेल्वे पुलिस ने स्थानीय पुलिस को शव को सौंपा जिसके बाद स्थानीय पुलिस ने शव को पी.एम के लिए भेज दिया। सचिन जी.आई.डी.सी पुलिस द्वारा अभी तक मिल मालिक के खिलाफ किसी भी प्रकार की कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। मो. सरीफ के परिवार के लोगों द्वारा संगम मिल के गेट पर जाकर उचित मुआवजे के लिए शांति पुर्वक प्रदर्शन किया गया।

मृतक मो. सरीफ

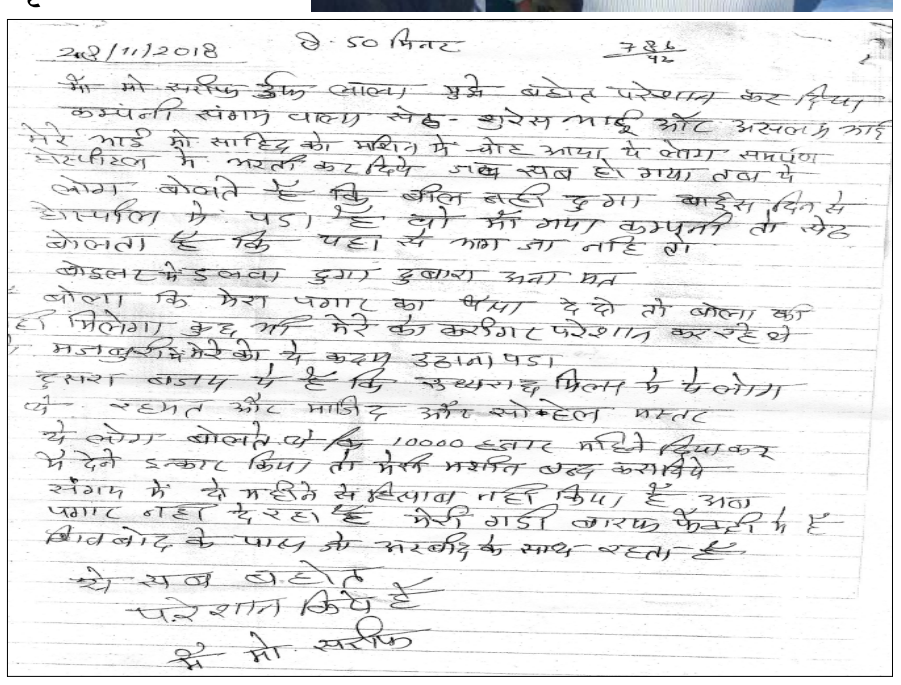

28/11/2018 9.50 मिनट 786/92

मैं मो सरिफ बोलता मुझे बहोत परेशान कर दिया
कम्पनी संगम वाला सेठ- सुरेस भाई और असलम भाई
मेरे भाई मो साहिद को मशीन मे चोट आया ये लोग समर्पण
होस्पीटल मे भरती कर दिये जब सब हो गया तब ये
लोग बोलते है कि बील नही दुगा बाईस दिन से
होस्पीटल मे पडा है वो मैं गया कम्पनी तो सेठ
बोलता है कि यहा से भाग जा नहि तो
पोलिस मे डलवा दुगा दुबारा आना मत
बोला कि मेरा पगार का पैसा दे दो तो बोला की
नही मिलेगा कुछ भी मेरे को करीगर परेशान कर रहे थे
मजबुरी मे मेरे को ये कदम उठाना पडा
दूसरा वजह ये है कि सुखसागर मिल के ये लोग
ये रहमत और माजिद और सोहेल मस्तर
ये लोग बोलते थे कि 10000 हजार महिने दिया कर
मैं देने इन्कार किया तो मेरी मशीन बन्द करवा दिये
संगम मे दो महिने से हिसाब नही किया है अत
पगार नही दे रहा है मेरी गाडी तारक फैक्टरी मे है
शिवबोद के पास जो अरबिंद के साथ रहता है
ये सब बहोत
परेशान किये है
मैं मो सरिफ

सचिन रेल्वे स्टेशन से खुलेआम दारु की खेप मारते बुटलेगर

सूरत। बुधवार को दोपहर मेमों. ट्रेन से खुले आम स्टेशन पर इस तरप से बुटलेगर खेप मारते है। लेकिन ये सब ना तो स्थानीय पुलिस को दिख रहा है ना ही जीआरपी और आरपीएफ को। ये दारु की खेप मरने वालो के उपर प्रशासन का पुरा हाथ है जिससे अगर कोई इनके खिलाफ फरियाद दाखिल करता है तो भी उन्हे पहले ही सुचना मिल जाती है और वे उस दिन अपना माल किसी अन्य जगह पर उतार लेते है।

गुजरात में ठंड बढ़ी, सूरत में तापमान 20.1 डिग्री पर पहुंचा

सूरत। शहर समेत राज्यभर में पिछले तीन दिनों से ठंड में उत्तरोउत्तर वृद्धि हो रही है। आमतौर पर नवरात्रि से गुलाबी ठंड शुरू हो जाती है, लेकिन इस साल नवंबर के अंत में ठंड महसूस की जाने लगी है और रात-दिन यह लगातार बढ़ती जा रही है। मध्य गुजरात के वडोदरा में आज सर्वाधिक ठंड महसूस की गई, जहां तापमान गिरकर 15.2 डिग्री पर पहुंच गया। वहीं अहमदाबाद में तापमान 16.4 डिग्री, डीसा में 16.2 डिग्री, सूरत में 20.1 डिग्री, वलसाड में 16.6 डिग्री, अमरेली में 19 डिग्री, द्वारका में 22.4 डिग्री, ओखा में 26.4 डिग्री, पोरबंदर में 21.6 डिग्री, राजकोट में 22.4 डिग्री, सुरेन्द्रनगर में 19 डिग्री, महुवा में 17 डिग्री और नलिया में न्यूनतम तापमान 16.6 डिग्री दर्ज हुआ।

शहर के अलग-अलग क्षेत्रों में आंगनवाडी की अपेक्षा से कम तरीके से सक्रिय हुई है। नवावाडज वोर्ड की आंगनवाडी की हालत भी बदतर है।

14 साल की किशोरी को डरा-धमकाकर 11 महीनों तक दुषकर्म

राजकोट। शहर के नानामहुवा क्षेत्र में 14 साल की किशोरी को प्रेमजाल में फांसकर एक विवाहित श स ने 11 महीनों तक उसके साथ दुष्कर्म किया। 11 महीनों बाद किशोरी की शिकायत के आधार पर महिला पुलिस ने मामले की जांच शुरू की है। जानकारी के मुताबिक राजकोट के नानामहुवा क्षेत्र में रहनेवाली 14 साल की किशोरी अन्य घरों में काम कर अपने परिवार को आर्थिक मदद करती है। पड़ौस में रहनेवाले विवाहित अमित विनोद मकवाणा नामक श स ने किशोरी को अपनी प्रेमजाल में फंसा लिया। गत 14 जनवरी 2018 को मकर संक्रांति को अमित ने किशोरी को अपने घर में बुलाया और उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया। साथ ही अमित मकवाणा ने घटना के बारे में किसी से शिकायत करने पर किशोरी को उसके पिता को जान से मार देने की धमकी दी। धमकी के डर से किशोरी ने घटना का किसी से जिक्र नहीं किया। जिसका अमित पूरा फायदा उठाया और 11 महीनों तक किशोरी को अपने घर में कई घंटों बंधक बनाकर उसके साथ दुष्कर्म करता रहा। दो दिन पहले अमित ने किशोरी को फिर डराने धमकाने की कोशिश की।

17992 किसानों से 3.60 लाख क्विंटल मूंगफली की खरीदी

अहमदाबाद। गुजरात में समर्थन मूल्य पर 17992 किसानों से 27 नवंबर तक रु. 180.25 लाख कीमत की 360515 क्विंटल मूंगफली खरीदी गई है। गुजरात के नागरिक आपूर्ति निगम के राज्य सरकार द्वारा खरीफ सीजन 2018-19 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मूंगफली की खरीद 15 नवंबर 2018 से शुरू की गई थी। मंगूफली के खरीद केन्द्र के तौर पर राज्यभर के कुल 122 एपीएमसी सेंटर पर संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा 1 नवंबर 2018 से किसानों से समर्थन मूल्य पर मूंगफली खरीदने के लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू की गई थी। पंजीकरण के मुताबिक सरकार के नियमानुसार प्रति दिन 2500 किलो की सीमा में मूंगफली लाने की एसएमएस के जरिए किसानों को सूचना दी गई थी। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य प्रति क्विंटल रु. 5000 के मुताबिक राज्यभर में 17992 किसानों से कुल रु. 180. 25 लाख की 160515 क्विंटल मूंगफली की खरीद की गई है।

नेपाल के कानून और जटिलता के बीच शाह फंसे

विनय शाह को अहमदाबाद लाने में अभी देरी की संभावना

नेपाल में गिरफ्तार हुए विदेशी मुद्रा मूल्य की तीन गुना रकम चुकाए तो विनय शाह तब बरी हो सकेगा : रिपोर्ट

अहमदाबाद। एक के डबल करके देने की लालच देकर लाखों निवेशकों के २६० करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने वाले विनय शाह को नेपाल से यहां अहमदाबाद लाने में अभी देरी होने की संभावना है । नेपाल के कानून और जटिलताओं के बीच विनय शाह वहां फंसे हुए हैं। भारत विशेष करके गुजरात की जांच एजेन्सी विनय शाह को जल्दी से गिरफ्तार करने के लिए इंतजार कर रही है। विनय शाह नेपाल में गिरफ्तार हो गया हो, लेकिन इसे नेपाल से वापस लाने काम इतना आसान नहीं है । भारत- नेपाल के बीच १९६३ की साल में हुई प्रत्यर्पण संधि ही विनय को वापस लाने के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा बन रही है । विनय को जल्दी से भारत लाने के लिए सीआईडी क्राइम कुछ भी दावा करे लेकिन सच्चाई है कि जिस अपराध के तहत दोनों देश फरार आरोपियों को एक-दूसरे को सौंप सके इसमें वित्तीय गड़बड़ी या धोखाधड़ी में शामिल अपराधियों को परस्पर सौंपने का कोई उल्लेख नहीं है । पुलिस के मुताबिक विनय शाह और उसकी पत्नी ईमेल के जरिये ठगी की वारदात को अंजाम देते थे ।

दोनों ईमेल से घर बैठे ऑनलाइन विज्ञापन देकर निवेश की राशि को चंद महीनों में ही दो से तीन गुना करने का लालच देते थे । अहमदाबाद में विनय शाह और भार्गवी शाह के खिलाफ १० एफआईआर दर्ज हो चुकी है । दोनों आर्चर केयर डीजी एलएलएलपी, वर्ल्ड क्लेवर एक्स सॉल्यूशन नाम की कंपनी चलाते थे । ४५००, ९५००, २५००० रुपये के तीन स्कीमें कंपनी चलाती थी । इसी राशि को दो-तीन गुना करने का सांझा देकर पति-पत्नी लोगों को चूना लगाते थे । अहमदाबाद के वस्त्रापुर के थलतेज में प्रेसिडेन्ट प्लाजा में आर्चर केयर के कार्यालय को पुलिस ने सील कर दिया है । विनय शाह के पासे से लोपटोप, चार मोबाईल, छह एटीएम कार्ड और लाखो रुपये की फोरेन करन्सी मिलने के बाद इस मामले में भी जांच शुरू हो चुकी है । महाठग के रूप में चर्चा में आए विनय शाह की गिरफ्तार के बाद जिन लोगों ने अपने पैसे गवाये है उन लोगों को पैसे मिलने की आशा अब बढ़ गई है ।

काफी प्रयास के बाद आग को नियंत्रण में लिया गया

गोंडल मार्केटिंग यार्ड में मिर्ची की हजारों बोरियों जलकर खाक

अहमदाबाद । मार्केटिंग यार्ड में आग लगने की और एक घटना राज्य में हुई थी जिसे लेकर गुजरात की राजनीति में हलचल तेज हो गई थी । बुधवार को राजकोट की गोंडल मार्केटिंग यार्ड में भीषण आग लग गई थी । मार्केटिंग यार्ड में मिर्ची की हजारों बोरियों का स्टोक था जिसमें अचानक किसी वजह से आग लग गई थी । यह भीषण आग में मिर्ची की हजारों बोरी जलकर खाक हो गई थी । यह आग ने भयंकर रूप धारण कर लिया, जिसके कारण मार्केटिंग यार्ड में अराजकता माहौल पैदा हो गया । आग में मिर्ची की ४ हजार से ज्यादा बोरी जलकर खाक हो जाने से करीब एक से डेढ़ करोड़ रुपये का नुकसान होने का अनुमान लगाया जा रहा है। दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी भाजपा सरकार निशाना साधते हुए कहा है कि, भाजपा सरकार मार्केटिंग यार्ड के घोटाले को छिपाने के लिए आग के बहाने किसानों को नुकसान पहुंचा रहे है। सौराष्ट्र में गोंडल मार्केटिंग यार्ड की तुलना बड़े यार्ड में होती है। अब फिलहाल मिर्ची की सीजन चल रही होने से किसान मिर्ची की बिक्री के लिए गोंडल मार्केटिंग यार्ड में आते हैं। किसी वजह से मिर्ची की हजारों बोरियों में आग लगने से अराजकता माहौल पैदा हो गया और बड़ी संख्या में लोग बाहर आ गये। घटना की जानकारी मिलते ही गोंडल फायरब्रिगेड के फाइटर पहुंच गये थे और घंटों की मेहनत के बाद आग को नियंत्रण में लिया गया। आग से किसानों और व्यापारियों को लाखों का नुकसान होने की जानकारी मिल रही है। धुआं से लोगों के आंख में जलन होने लगी तथा गले में असर हुई थी। आग के कारण किसानों को काफी नुकसान भुगतना पड़ेगा।

कपास की फसल विफल जाने से एक किसान ने की आत्महत्या

अहमदाबाद । गुजरात में और एक किसान ने आर्थिक समस्या सामने हार गया, उसने आत्महत्या कर ली । सुरेन्द्रनगर सायला तहसील की सांगोई गांव के किसान ने कपास की फसल विफल जाने से गले में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली । पिछले १५ दिन में सायला तहसील में फसल विफल जाने पर दूसरे किसान ने आत्महत्या कर ली है। पिछले तीन महीने में देखे तो १७ से ज्यादा किसानों ने राज्य में आत्महत्या की है। इस तरह, राज्यभर में एक के बाद एक किसानों की आत्महत्या की वजह से सनसनी मच गई। दूसरी तरफ, प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता डॉ. मनीष दोशी ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि, भाजपा सरकार वाइब्रेंट और निजी प्रसिद्धि के पीछे करोड़ों रुपये के खर्च किए गए हैं और दूसरी तरफ, किसान फसल और फसल बीमा नष्ट होने की वजह से आत्महत्या करने के लिए मज बूर बन गये है फिर भी गुजरात की यह संवेदनहीन सरकार इस पर ध्यान नहीं देती है। सत्ता के नशे में कृषि विरोधी नीति के द्वारा किसानों को आत्महत्या करने के लिए प्रेरणा दे रही भाजपा सरकार को किसानों की बददुआ लगेगी । आगामी लोकसभा चुनाव में किसानों और पूरे गुजरात की ज नता भाजपा की सरकार को ज बाब देगी यह निश्चित है। किसानों की आत्महत्या के बारे में मिली जानकारी के अनुसार, सुरेन्द्रनगर के सांगोई के मनसुख करसनभाई नाम के किसान ने आत्महत्या कर ली है।

जसदण उप चुनाव के पहले स्थानीय पाटीदार में नाराजगी

अहमदाबाद । जसदण उप चुनाव को अब कुछ ही दिन बाकी रहे है । अब कांग्रेस की परेशानी में लगातार वृद्धि हो रही है । भाजपा के कुंवरजी बावलीया के विरूद्ध उम्मीदवार निश्चित नहीं कर सके कांग्रेस से स्थानीय पाटीदार नाराज होने का सामने आया है । इतना ही नहीं इस मामले में राज कोट तहसील कांग्रेस के पाटीदार अग्रणी ने प्रदेश अध्यक्ष अमित चावडा को पत्र लिखा है। यह पत्र में बताये अनुसार, कांग्रेस पाटीदारों को लगातार नजरअंदाज करती है और चुनाव के समय साथ में होने का वादा करने के बाद उनको भुल जाते है। पाटीदार अग्रणी ने लिखे इस पत्र को लेकर स्थानीय राज नीति में हलचल तेज हो गई है । जसदण उप चुनाव के पहले ही स्थानीय पाटीदारों में गंभीर नाराज गी सामने आने पर कांग्रेस के प्रभारी सातवे भी पूरे मामले को गंभीरता से लिया गया और इस मुद्दे पर तुरंत विपक्ष के नेता परेश धानाणी को बुलाया था और उनके साथ सविस्तार चर्चा की । प्रभारी राजीव सातवे विपक्ष के नेता परेश धानाणी के साथ बैठक करके डेमेज कंट्रोल और नाराजगी दूर करने की महत्व की सूचना दिए जाने की जानकारी मिल रही है ।

स्वामी, मुद्रक व प्रकाशक सुरेश मौर्या द्वारा अष्ट विनायक ऑफसेट एफपी. 149, प्लोट 26 खोडियार नगर, सिद्धीविनायक मंदिर के पास, (भाटेना) हॉ.सो. अंजना सूरत, गुजरात से मुद्रित, एवं 191 महादेव नगर, हरि नगर-2 के पीछे, उधना, जिला-सूरत, गुजरात से प्रकाशित,
संपादक :- सुरेश मौर्या फोन नं. (9879141480) **RNI.No. : GUJHIN/2018/75100**, E-mail: krantisamay@gmail.com (subject to surat jurisdiction)